उत्तर प्रदेश में सीधे डायल घुमा कर टलीफोन करने की व्यवस्था से वंचित प्रमाणीय मुख्यालय

2213. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन प्रमाणीय मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधा नहीं है; और

(ख) अब तक यह सुविधा वहां न देने के क्या कारण हैं और यह सुविधा वहां कब तक दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख). गोरखपुर, झांसी, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में अभी तक आटोमेटिक एक्सचेंज नहीं हैं।

आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर की निहायत कमी है। इसलिए मैनुअल एक्सचेंजों को विभिन्न चरणों में आटोमेटिक बनाया जा रहा है। ऊपर बताये गये एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाने का कार्यक्रम इस प्रकार है :–

(i) गोरखपुर : 2700 लाइनों के एक आटोमेटिक एक्सचेंज की स्थापना की जा रही है। आशा है कि यह एक्सचेंज इस महीने के अन्त तक चालू हो जाएगा।

(ii) झांसी : 7वीं योजना के दौरान आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने की संभावना है।

(iii) नैनीताल : वर्ष 1980–81 में आटोमेटिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है।

(iv) पौड़ी गढ़वाल : वर्ष 1981–82 में एक छोटा आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

देश में टैलेक्स एक्सचेंज

2214. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन नगरों और कस्बों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जिनमें टैलेक्स एक्सचेंज केन्द्र है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ऐसे केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और ये एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर आठ टैलेक्स एक्सचेंज हैं :––

आगरा, इलाहाबाद, देहरादून, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली और वाराणसी। 9वां टैलेक्स एक्सचेंज गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) 6ठी योजना में निम्नलिखित तेईस स्थानों में टैलेक्स-सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना है, बशर्ते कि वहां टैलेक्स कनेक्शनों की पर्याप्त मांग हो :––

अलीगढ़, बरेली, भदोही, गोरखपुर, झांसी, फैजाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर,

सिकन्दराबाद, सीतापुर, बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद, हल्द्वानी, हापुड़, हरिद्वार, मथुरा, मोदीनगर, मसूरी, रामपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर ।

Improving Telephone Service at Durgapur

2215. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the deteriorating conditions of Durgapur telephone services; and

(b) if so, the steps Government propose to take to improve the phone services at Durgapur?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). No Sir. The telephone services at Durgapur have not deteriorated. However, as a normal measure for effecting better service, overhaul of exchange plants and rehabilitation of subscribers' installations where necessary have been taken up.

Problems of Durgapur Steel Plant

2216. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that power and coal pose problems for Durgapur Steel Plant;

(b) if so, reaction of the Government thereto; and

(c) whether the Government are aware that the D.V.C. has failed to honour its commitment in regard to the supply of power?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Yes, Sir.

(b) The problems are being taken up and pursued with the appropriate agencies.

(c) Yes, Sir.

Enforcement of minimum wages for Agriculture Labourers

2217. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to refer to the reply given to the Starred Question No. 161 on the 24th November, 1977, regarding enforcement of minimum wages for agricultural labourers and state:

(a) whether Government are aware that in many regions/areas of many States fixed statutory minimum wages remain on paper only;

(b) whether Government are also aware that in many areas the agricultural labourers are not aware of the Government's new order enchancing the existing rates; and

(c) if so, what steps, if any, are being taken?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) A Statement showing latest minimum wage rates for agricultural workers prescribed under the Minimum Wages Act, 1948 and a statement indicating the actual daily wage rates (of annual averages) of Plough-man or field labour-men in different States for the year 1976-77 are laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1760/78).

(b) and (c). Government have already written to all the State Governments/Union Territories to take effective steps for giving wide publicity to the notified minimum wages. Some of the measures that have been taken include publicity through various mass media. The State Government